[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

के बाद में खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी 'कड़ाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सबसे सूखे इलाके बाड़मेर एवं जालौर में काम आएगा।

गुजरात ने सन् 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की अवहेलना करके खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित करके माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की कार्यवाही सन् 1966 में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने की माही ही एकमात्र कम खर्च में पानी पहुँचाने का उपाय है, परन्तु गुजरात द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उससे राजस्थान प्रांत के और विशेषतः बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असंतोष है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई का कडारना बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी भाग डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था।

राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में दिनांक 24-12-80 को तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री राव बीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई थी।

उक्त बैठक में एक समिति का गठन केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। जिस में दोनों राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को सम्मिलित किया गया था, ताकि दोनों राज्यों के दावों का अवलोकन किया जा सके और माही नदी के पानी का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर व जालौर में किया जा सके।

गुजरात सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने में विलम्ब किया जा रहा है जबकि दोनों राज्यों के बीच में स्पष्ट समझौता हो चुका है।

यह प्रश्न राजस्थान प्रांत के विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस अविलंबनीय प्रश्न को सिंचाई मंत्री एवं प्रधान मंत्री विशेष दिलचस्पी लेकर शीघ्र से शीघ्र निर्णय कराकर राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी अकाल पीड़ित बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुँचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कराकर हरा-भरा करने में सक्रिय कदम उठाएं।

(iv) UNSATISFACTORY TELEPHOE SERVICE IN JODHPUR.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में टेलीफोन व्यवस्था बहुत ही अस्त-व्यस्त हो गई है। टेलीफोन उपभोक्ता ट्रककाल करना तो दूर स्थानीय काल से भी बात नहीं कर पाते। डायल टोन 15-20 मिनट तक नहीं मिलना आम बात है एवं मिल जाने पर भी वांछित नंबर से बात नहीं हो पाती है। पिछले तीन वर्ष से लगातार यही

हालत बनी हुई है। स्थानीय अधिकारी-गणों को अनेकों बार शिकायतें करने के बावजूद भी व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जोधपुर नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित मण्डोर एक्सचेंज की तो और भी हालत खराब है जहां से स्थानीय काल दिन भर की मेहनत के बाद 5, 7 मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अधिकांश कर्मचारी लापरवाही से जवाब देकर आम उपभोक्ताओं को परेशान करने पर तुले हुए हैं एवं नए टेलीफोन को लगाते वक्त एवं शिफ्ट करने में उपभोक्ताओं से भारी रकम वसूल करने में लगे हुए हैं। स्टोर में सामान की कमी के कारण भी नए एक्सचेंज एवं जिनका नम्बर आ जाता है वहां भी टेलीफोन नहीं लगाया जा रहा है। अतः संचार मंत्री जी से निवेदन है कि जोधपुर शहर की टेलीफोन व्यवस्था सुधारने हेतु अविलंब कार्यवाही करें।

(V) UNSATISFACTORY WORKING OF ATOMIC POWER STATION OF KOTA, RAJASTHAN.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : राणा प्रताप सागर में राजस्थान एटामिक पावर स्टेशन में शुरू से निरंतर टैक्नीकल खराबी के कारण अणु शक्ति विभाग को धन, समय और जन शक्ति के रूप में काफी बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके बन्द रहने से प्रतिदिन 29 लाख 40 हजार रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। उत्पादन क्षमता का चालीस प्रतिशत काम चलने पर भी हानि उतनी ही हो रही है। यदि हम इस सम्बन्ध में कुल लागत, वार्षिक खर्च, पूंजी, व्यय आदि का ब्योरा तैयार करें तो हानि की रकम बहुत अधिक होगी। राजस्थान एटामिक पावर स्टेशन की दोनों इकाइयों में विगत दस वर्षों में 225 बार रुकावटें आईं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक चौदह दिन बाद इन इकाइयों को बन्द करना पड़ा। इस पर स्थापना के समय प्रारम्भ में 175 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसके संचालन पर 1981-82 में 46 करोड़ रुपये खर्च हुए। इन सब का परिणाम यह है कि इसमें पैदा होने वाली बिजली उपभोक्ताओं को न तो नियमित रूप से मिलती है और न ही उचित कीमत पर। इसमें डिजाइन सम्बन्धी नुक्स भी हैं। हैवी वाटर को स्टोर करने की समस्या और लीकेज, ये दो प्रमुख समस्यायें हैं। विकिरण यानी रेडिएशन के कारण कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी वहां ज्यादा नहीं रुकते।

राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी है। डा० एन० बी० प्रशाद राजस्थान में एटामिक पावर स्टेशन का टेक्नालाजिकल लेखा-जोखा तैयार कर रहे है। यह रिपोर्ट पहली जुलाई को प्रस्तुत की जानी थी किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवा कर उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए और अणु बिजली घर को स्थायी आधार पर निर्विघ्न रूप से संचालित किया जाए ताकि राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रगति हो सके।

(vi) PROPER MAINTENANCE OF FOOD-GRAINS BY FOOD CORPORATION OF INDIA.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : भारतीय कृषकों के अथक परिश्रम से उत्पादित अन्न की खरीद के पश्चात उचित देखरेख न होने व भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसको उचित स्थानों पर न पहुंचाने के कारण करोड़ों रुपये मूल्य का अन्न खराब